Extension to Officers

2776. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the names and ranks of officers in each Ministry who are covered under the List of Precedent of Warrant and were given extensions during the years 1989, 1990, 1991 and 1992; and

(b) the nature of the jobs held by them at the time they attained the age of retirement?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) and (b) Officers at the level of Joint Secretary and higher levels working in the Ministries are covered under the Table of Precedence. A statement indicating the names of officers who were given extensions beyond superannuation during the years 1989, 1990, 1991 and 1992, is attached herewith.

Statement

S. No.	Name of the Officers	Post held by the officers at the time of superannuation
1	2	3
		1989
1.	Shri K.P.S. Menon	Foreign Secretary, Ministry of External Affairs.
2.	Shri S. Venkiteramanan	Finance Secretary, Ministry of Finance.
3.	Shri B.G. Deshmukh	Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat.
4.	Dr. A.P. Mitra	Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.
		1990
5.	Shri S.K. Singh	Foreign Secretary, Ministry of External Affairs.
6.	Shri M.N. Prasad	Chairman, Railway Board and ex-officio Principal Secretary.
7.	Shri V.C. Pande	Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat.
		1991
8.	Shri S.K. Mistra	Principal Secretary to the then Prime Minister in the Prime Minister's Office.
		1992
		NIL

2777. *[Transferred to 18th Dec. 1992]*

Annual Plan Out Lay for Arunachal Pradesh

2778. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the percentage of plan money spent during the financial year 1989-90, 1990-91 and upto September, 1992 for Arunachal Pradesh;

(b) whether it is a fact that the proposed plan money could not meet the required development activities;

(c) whether State Government was forced to adopt "Overdraft" to meet the entire plan's requirements; and

(d) if so, the reasons therefor, and if not, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) The State Government has reported an expenditure of 102.72 percent in 1989-90 and 90.65 per cent in 1990-91. The expenditure upto September, 1992 is not available.

(b) Plans are prepared on the basis of resources and having regard to the needs of development.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise

ग्रामीण व्यक्ति की औसत आय

2779. **श्री राम सिंह राठवा**: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष ग्रामीण व्यक्ति की औसत आय कितनी थी;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उसकी औसत आय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) ग्रामीणों की आमदनी में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) 1970-71 तथा 1980-81 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय का अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) में तैयार किया गया है तथा जुलाई 1989 की मन्थली एब्सट्रैक्ट आफ स्टेटिसटिक्स में प्रकाशित किया गया। वर्तमान कीमतों पर ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद 1970-71 तथा 1980-81 में क्रमशः 499.4 तथा 1242 रुपए था। पिछले वर्ष के लिए देश के एक ग्रामीण की औसत आय तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान उसकी वृद्धि के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विकास के लिए तथा ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के लिए भी विकास स्कीमों तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। उत्पादकता तथा कृषि में वृद्धि करने तथा आय बढ़ाने की दृष्टि से फसल उत्पादन, मुद्रा संरक्षण, बागवानी, पशु पालन, मछली पालन, रोपड़ फसलें, अनुसंधान सहकारिता तथा ऋण के लिए विशेष स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए कई कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडी पी) तथा जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) शामिल हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) तथा जनजाति उपयोजना (टीएसपी) कार्यान्वित की जा रही है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं

2780. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु परियोजनाओं/योजनाओं की कोई सूची भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं/योजनाओं को विश्व बैंक की सहायता से अलग से कार्यान्वित किया जाएगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए कई परियोजनाओं/स्कीमों से युक्त प्रारूप आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 तथा वार्षिक योजना 1992-93 प्रस्तुत किया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 21000 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।